प्रेषक.

टीकम सिंह पँवार, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2008

विषय:- यात्रा मार्गो के पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 4977/अप्रै/03/यात्रा व्यवस्था पे0/2007-08 दिनांक 10.12.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम यात्रा मार्गो पर यात्रा के दौरान यात्रियों को समुचित पेयजल उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित कार्यो हेतु रू० 112.50 लाख के प्राक्कलन पर टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू० 111.87 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू० 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(I) आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन

आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(II) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगंणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(III) कार्य पर उतना हैं। व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(IV) एक मुश्त प्राविधान को, कार्य करने से पूर्व, विस्तृत ब्यौरा गठित कर समक्ष अधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

(V) अांगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर

व्यय किया जाये एक मद की राशि को दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(VI) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें ।

(VII) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली—भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों

तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(VIII) जी0पी0डब्ल्यू० फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगंणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

42

(IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(X) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन स्थानों पर जिला योजना या स्टेट सैक्टर में हैण्ड पम्प पूर्व में लगाये जा चुके हैं, उन्हीं स्थानों पर पुनः न लगाया जाय और यदि लगाया जाना हो तो उसकी आवश्यकता के लिए सन्तुष्ट होने पर ही लगाया जाय।

- (XI) प्रमाण यह दिया जाय कि कार्य यात्रा प्रारम्भ होने के समय या यात्रा प्रारम्भ होने के शिधातिशीध पूर्ण कर लिया जाय, ताकि यात्रा मार्ग पर पर्यटक व यात्रियों को अविलम्ब इसका लाभ प्राप्त हो सके।
- 2— स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार दो बराबर किश्तों में प्रथम किश्त का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।
- 3— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या ए—2—87(1) दस—97—17(4)/75 दिनांक 27—02—97 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जेज के रुप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगंणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।
- 4— कार्य उक्त लागत में निर्धारित समयाविध में पूर्ण कर लिया जायेगा और इस लागत में किसी भी प्रकार का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
- 5— कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- 6— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-06-चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गो पर पेयजल उपलब्ध कराना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।
- 7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 798/XXVII(2)/ 08 दिनांक 13 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय,

(टीकर्म सिंह पँवार) संयुक्त सचिव

पृ०स० 428 / उन्तीस(२) / ०४-(१०१पे०) / २००५ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....3

- 2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
- 3. जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- 6. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / नोंडल अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
- 8. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड।
- 9. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य संचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 10. निर्देशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निर्देशालय, देहरादून।
- ्रा. निदेशक, एन0आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(नवीन सिंह तड़ागी) उप सचिव